an>

Title: Need to increase the coverage under the National Food Security Scheme in Rajasthan.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) ः मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के 69.09 प्रतिशत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जबकि राजस्थान की तुलना में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध राज्यों में प्रतिशत कवरेज अधिक है। गुजरात में 74.64 प्रतिशत, कर्नाटक में 76.04 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 76.32 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 82.55 प्रतिशत। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 79.56 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 74.47 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 84.25 प्रतिशत, बिहार में 85.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का पुनः निर्धारण किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इस मुद्दे पर दिनाँक 15.06.2016 को नीति आयोग, नई दिल्ली में बैठक में चर्चा की गई। जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी अपने पत्र दिनाँक 09.08.2016 के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनुरोध किया जा चुका है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का शीघ्र पुनः निर्धारण करने की कृपा करें।